



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939

No. 166]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

मामला सं.एसएसआर 11/2017

विषय : चीन जन. गण. और थाइलैंड से “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) के आयात पर निर्णयिक समीक्षा जांच की शुरूआत।

सं 7/7/2017 डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण और थाइलैंड,(जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम सं. 14/34/2010-डीजीएडी दिनांक 22 मई, 2012 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम सं. 36/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 16 जुलाई, 2012 के अनुसार शुल्क लागू किए थे।

2. और जबकि मै. एआईए इंजीनियरिंग लि. और बेबकास्ट स्टील्स लि.(जिन्हें इसके बाद “याचिकाकर्ता” कहा जाएगा) की अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, चीन और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध

वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहने और उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाते हुए, शुल्कों को और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) के आयात पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है।

क. शामिल देश

3. चीन जनवादी गणराज्य और थाइलैंड इस जांच में शामिल देश हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में है जिसे “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) के रूप में परिभाषित है। “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (संक्षेप में “जीएम बाल्स”) का विविध अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए अलग-अलग आकारों, आकृतियों और संरचनाओं में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा, यह ग्राहकों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अलग-अलग कठोरताओं (हार्डनैश) में उपलब्ध है। संबद्ध वस्तु सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमाशुल्क उपशीर्षक 73259100 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और किसी प्रकार से इस जांच के कार्यक्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।

5. प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद का निम्नानुसार वर्णन किया है:-

8. विचाराधीन उत्पाद “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (फोर्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) है। “ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स” (संक्षेप में “जीएम बाल्स”) का विविध अनुप्रयोगों में उपयोग करने के लिए अलग-अलग आकारों, आकृतियों और संरचनाओं में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा, यह ग्राहकों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अलग-अलग कठोरताओं (हार्डनैश) में उपलब्ध है।

9. विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग सीमेंट निर्मित सामग्री, धातु खान, कोयला घोल, ताप विद्युत संयंत्र, रसायन इंजीनियरी, सिरेमिक उद्योग, रोगन (स्नेहक) उद्योग, हल्के उद्योग जैसे कांगज बनाना और पाउडर तैयार करने के लिए चुम्बकीय सामग्री में किया जाता है। संबद्ध वस्तु सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमाशुल्क उपशीर्षक 73259100 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और किसी प्रकार से इस जांच के कार्यक्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।

6. चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा कि पूर्व जांच में दिया गया है।

ग. समान वस्तु

7. समान वस्तु के संबंध में नियम (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत हैं जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान हैं अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

8. याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित और घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विशेषताओं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे मानदंडों के अनुसार समान विशेषताएं हैं।

(घ) घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. मै. एआईए इंजीनियरिंग लि. और वेबकास्ट स्टील्स लि. के द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने देश में विचाराधीन उत्पाद के बड़े उत्पादक होने का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातिक से संबंधित नहीं हैं अथवा उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और इसलिए नियमावली के अर्थ के भीतर “घरेलू उद्योग” के रूप में माने जाने के लिए पात्र हैं। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता कंपनियों को माना है और उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

(ड.) निर्णयिक समीक्षा की प्रारंभिक जांच

10. विधिवत प्रमाणित दायर आवेदन को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगाना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए जांच शुरूआत की है कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तुओं का पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

च. जांच की अवधि

11. प्राधिकारी ने जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 मानी है। तथापि क्षति जांच अवधि 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच अवधि मानी गई है।

छ. प्रक्रिया

12. वर्तमान निर्णयिक जांच समीक्षा में अधिसूचना सं. 14/34/2010-डी जी ए डी दिनांक 22 मई, 2012 के द्वारा प्रकाशित मूल जांच परिणामों के अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होते हैं, जिसमें चीन जनवादी

गणराज्य और थाइलैंड के मूल के और वहां से निर्यातित ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

13. इस समीक्षा में ऊपर बताई गई नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपर्युक्त आवश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में निर्यातिकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध उत्पादों से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 01, चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001
dgad.india@gov.in

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

16. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्यास विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**Department of Commerce**

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th, July, 2017

Case NO. SSR- 11/2017

Subject: Initiation of Sunset review investigation concerning imports ‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls) from China PR and Thailand.

F. No. 7/7/2017-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of “‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls)”, (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Thailand (hereinafter referred to as subject Countries). The authority vides its final findings No 14/34/2010-DGAD dated, 22nd May 2012 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the Subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 36/2012-Customs (ADD) dated the 16th July, 2012.

2. And whereas, a petition has been jointly filed by M/s AIA Engineering Ltd and Webcast Steels Ltd (hereinafter referred to as petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of “‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls) ”, for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR and Thailand.

A. Countries Involved

3. The country involved in this investigation is China PR and Thailand.

B. Product under consideration and like article

4. The product under consideration is the same as the original investigations which is defined as ‘Grinding Media Balls’ (excluding Forged Grinding Media Balls). ‘Grinding Media Balls’ (in short, ‘GM Balls’) are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available in different hardness depending upon varying requirements of the customers. The subject good is classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

5. The Authority described product under consideration as follows in the final findings of the original investigation is as under:

8. The product under consideration is 'Grinding Media Balls' (excluding Forged Grinding Media Balls). 'Grinding Media Balls' (in short, 'GM Balls') are produced in different sizes, shapes and compositions for use in diverse applications. Further, it is available in different hardness depending upon varying requirements of the customers.

9. The product under consideration is extensively used in cement build materials, metal mine, coal slurry, thermal power plant, chemical engineering, ceramic industry, dope industry, light industry such as papermaking and magnetic material etc for powder preparation. The subject goods are classified under Customs sub-heading 7325 9100 of Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

6. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of the previously concluded investigation.

C. Like Article

7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

8. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.

D. Domestic Industry and Standing

9. The petition has been filed by M/s AIA Engineering Ltd and Webcast Steels Ltd. Petitioners claim to be the major producers of the product under consideration in the Country. The petitioners have certified that they are not related to producer/exporter of the product under consideration in subject countries or have imported the subject good from the subject countries during the Period of investigation and therefore is eligible to be treated as "domestic industry" within the meaning of Rules. The Authority has considered the petitioner companies as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

E. Initiation of Sunset Review

10. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject

goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

F. Period of Investigation

11. The Authority has considered the period of April 2016-March 2017 as the Period of investigation. The injury investigation period has however, been considered as the period 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.

G. Procedure

12. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original findings published vide Notification No. No 14/34/2010-DGAD dated, 22nd May 2012 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Grinding Media Balls originating and exported from China PR and Thailand.

13. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of information

14. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address.

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001.
dgad.india@gov.in

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

I. Time Limit

16. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record

its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of information on confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of public file

24. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. Non-cooperation

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. Inder Jit Singh, Designated Authority